



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1122]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2004/पौष 10, 1926

No. 1122]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2004/PAUSA 10, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1436(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 फ प (वी यू) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय- XII -छ (जी) के अनुसार टनभार कर-प्रणाली अपना चुनने वाली नौवहन कम्पनियों द्वारा प्रशिक्षण सुलभ करवाए जाने के बारे में, एतद्वारा 01 जनवरी, 2005 से प्रभावी निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त अधिसूचित करती है :-

1. टनभार कर चुनने वाली कम्पनी सभी जहाजों पर अथवा अपने किसी भी अर्हकारी जहाज पर प्रशिक्षणार्थी अधिकारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण से संबंधित कार्य के कुल दिन, न्यूनतम प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षा पूरी करने की दृष्टि से आवश्यक प्रशिक्षण के कार्य के दिनों से कम नहीं हों।

स्पष्टीकरण :

इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रयोजन से,

(क) प्रशिक्षणार्थी अधिकारी का अभिप्राय, नौवहन-महानिदेशक द्वारा प्रकाशित समुद्री-शिक्षण और प्रशिक्षण-आकलन के बारे में नियम - पुस्तक में विनिर्दिष्ट अथवा नौवहन-महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार समुद्र में चल रहे जहाज पर कार्य करना आरंभ करने की दृष्टि से अपेक्षित अर्हताएँ रखने वाला व्यक्ति है।

(ख) न्यास का अभिप्राय, भारतीय राष्ट्रीय पोत-स्वामी-संघ के परामर्श से, नौवहन-महानिदेशालय द्वारा स्थापित समुद्री प्रशिक्षण न्यास है।

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यकता निम्नानुसार होगी :

- (1) टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी के अपने ही जहाज अथवा चार्टर किए गए जहाज (स्पेस अथवा स्लॉट चार्टरों को छोड़कर) के मामले में प्रशिक्षण से संबंधित कार्य के दिनों की संख्या, किसी वित्तीय वर्ष में टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा ऐसे जहाज चलाए जाने के दिनों को (1) न्यूनतम सुरक्षा-जन-प्रबंध-दस्तावेज के अनुसार अथवा उसके यथानुपात में प्रत्येक दस (10) अनुपूरक के संबंध में एक (1) प्रशिक्षणार्थी अधिकारी के आधार पर, अपेक्षित प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों की संख्या से गुणा करने पर आने वाली संख्या के बराबर होगी;
- (2) स्पेस चार्टरों अथवा स्लॉट चार्टरों के मामले में, कार्य के दिनों की संख्या, टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी के स्लॉट / स्पेस चार्टरों के निवल टनभार में निवल टनभार गुणनखंड (फैक्टर) का भाग देकर और उससे आने वाली संख्या को टनभार चुनने वाली कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान जहाजों को चलाए जाने के दिनों की संख्या से गुणा करके एवं खण्ड 15 के अनुसार उस वित्त वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में रही, आगे लायी गयी कमी को शामिल करके परिकलित की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1 : इस खण्ड के प्रयोजन से, स्लॉट/स्पेस चार्टरों का निवल टनभार, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 फ छ (वी जी) के बारे में स्पष्टीकरण के संबंध में राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार यथा परिकलित निवल टनभार होगा।

स्पष्टीकरण 2 : निवल टनभार गुणनखण्ड (फैक्टर), नौवहन-महानिदेशालय द्वारा, वाणिज्यिक-पोत-परिवहन-अधिनियम, 1958 के अनुसार पंजीकृत सभी अर्हकारी जहाजों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष का, पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल निवल टनभार के रूप में परिकलित, अधिसूचित किया गया गुणनखण्ड (फैक्टर) होगा, जिसमें पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऐसे जहाजों की कुल संख्या का भाग दिया जाएगा और उसे नौवहन-महानिदेशक द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ होने के 60 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाएगा।

(घ) " भारतीय राष्ट्रीय पोत-स्वामी-संघ " का अभिप्राय, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार पंजीकृत भारतीय पोत स्वामी संघ है।

(इ) " वित्तीय वर्ष " का अभिप्राय, 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि से है।

2. टनभार कर चुनने वाली कम्पनी समुद्र में चल रहे सभी जहाजों अथवा अपने किसी अर्हकारी जहाज पर अपने निजी संसाधनों से, अथवा उपर्युक्त न्यास द्वारा रखे जा रहे रोस्टर में प्रशिक्षणार्थी

अधिकारी के रूप में पैनल में रखे गए प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों में से, प्रशिक्षणार्थी अधिकारी भर्ती करेगी और समुद्री-शिपिंग और प्रशिक्षण-आकलन के बारे में नियम-पुस्तक एवं/ अथवा नौवहन-महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को प्रशिक्षण सुलभ करवाएगी।

3. समुद्र में चल रहे जहाज पर ऐसे सभी प्रशिक्षणार्थी, न्यूनतम सुरक्षा-जन-प्रबंध-दस्तावेज के अनुसार काम पर रखे गए अधिकारियों के अतिरिक्त होंगे। समुद्र में चल रहे किसी अर्हकारी जहाज पर किसी भी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी का, नौवहन-महानिदेशक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सुरक्षा-जन-प्रबंध-दस्तावेज से संबंधित अपेक्षाएँ निश्चित करने के प्रयोजन से शुमार नहीं किया जाएगा।

4. ऐसे प्रशिक्षणार्थी अधिकारी द्वारा भुगतान किए जाने योग्य प्रशिक्षण-शुल्क और ऐसे प्रशिक्षणार्थी अधिकारी तथा टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा उपर्युक्त न्यास को भुगतान किए जाने योग्य प्रशासनिक लागत तथा टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को भुगतान किए जाने योग्य वृत्तिका की धनराशि, नौवहन-महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

5. खण्ड (4) के अनुसार, किसी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी द्वारा उपर्युक्त न्यास को भुगतान किए जाने योग्य छः (6) माह का प्रशिक्षण-शुल्क अग्रिम रूप से दिया जाएगा और किसी प्रशिक्षणार्थी द्वारा भुगतान किया जाने वाला ऐसा शुल्क तथा प्रशासनिक प्रभार, टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा उपर्युक्त न्यास के नाम से लिया जाएगा और उसे तुरंत उपर्युक्त न्यास के पास जमा करवा दिया जाएगा। टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी की, उपर्युक्त धनराशि मिलने के देर से देर सात (7) दिनों के भीतर उपर्युक्त धनराशि को उपर्युक्त न्यास के पास जमा करवा देने तथा उसका रेकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी होगी।

6. उपर्युक्त न्यास की निधि, नौवहन-महानिदेशक द्वारा कायम किए जाने वाले टनभार - कर -प्रकोष्ठ (सैल) से संबंधित प्रशासनिक व्यय वहन करने तथा भारतीय नाविक अधिकारियों के प्रशिक्षण और नियोजन के संवर्धन तथा खण्ड 10 के अनुसार शुल्क की वापसी का भुगतान करने हेतु प्रयुक्त की जा सकेगी।

7. किसी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को प्रशिक्षण सुलभ करवाया जाना, ऐसा प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने अथवा समाप्त हो जाने पर, ऐसे प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को नौकरी दे दिए जाने की गारंटी के रूप में नहीं माना जाएगा।

8. किसी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण लेना पूर्ण कर लिए जाने पर, उसके द्वारा टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा यथा अपेक्षित अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी में कार्य किया जाना अपेक्षित होगा। प्रशिक्षणार्थी अधिकारी द्वारा यह दायित्व पूरा नहीं कर लिए जाने तक वह विश्व में किसी भी अन्य नौवहन कम्पनी में कार्य करने का पात्र नहीं होगा और उसे प्रशिक्षण हेतु स्वीकार किए जाने से पहले टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी के पक्ष में इस आशय का वचनबंध-पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु, यदि टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी ने उसके द्वारा प्रशिक्षण पूरा कर लिए जाने के एक माह के भीतर उसे नौकरी नहीं दी तो यह शर्त लागू नहीं होगी।

9. जिस मामले में कोई प्रशिक्षणार्थी अधिकारी, टनभार-कर चुनने वाली किसी कम्पनी में अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने पर, उस कम्पनी में अवकाश की अवधि को घटाकर, कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक लगातार कार्यरत रहे तो उस मामले में वह ऐसी तीन वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेने पर अपने द्वारा उपर्युक्त न्यास को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी का दावा करने का हकदार होगा और उपर्युक्त न्यास द्वारा ऐसे शुल्क का भुगतान करके ऐसे दावे का निबटारा कर दिया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा दावा तीन वर्ष की अवधि पूर्ण कर लिए जाने के छः माह के भीतर कर दिया जाए और टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी से उस आशय का उपर्युक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाए।

10. यदि संबंधित टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को निरन्तर तीन क्रमिक वर्षों तक कोई नौकरी नहीं दी जाए तो प्रशिक्षणार्थी अधिकारी अपने द्वारा भुगतान किए गए शुल्क की वापसी की माँग करने का हकदार होगा, बशर्ते कि ऐसा दावा उस तारीख से छः माह के भीतर कर दिया जाए, जिस तारीख को नौकरी या अविच्छिन्न नौकरी नहीं दी गई हो।

11. निम्नलिखित अवधियाँ उस अवधि के रूप में मानी जाएँगी जिसके दौरान टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया -

(i) वह अवधि, जब टनभार-कर चुनने वाली किसी कम्पनी की, एक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी या अधिक प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों की अपेक्षाएँ, उपर्युक्त न्यास द्वारा रखे जा रहे रोजर में दर्ज अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण, उपर्युक्त न्यास द्वारा इस बारे में लिखित रूप से किसी अनुरोध

की पावती भेजे जाने की तारीख से ऐसे अनुरोध के उत्तर-स्वरूप प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धता की तारीख तक पूरी नहीं हो पाएँ।

(ii) वह अवधि, जब कोई प्रशिक्षणार्थी अधिकारी, समुद्र में चल रहे किसी अर्हकारी जहाज में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने में विलम्ब हो जाने के कारण अथवा टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी के नियंत्रण से परे, किसी भी अन्य कारण से विलम्ब हो जाने पर अनुपस्थित हो, जबकि ऐसे विलम्ब के बारे में संबंधित कम्पनी द्वारा नौवहन-महानिदेशक को सूचित कर दिया गया हो।

(iii) जिस मामले में प्रशिक्षण के अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो जाने के सिवाय, किसी अन्य कारण से प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाए तो उस मामले में प्रशिक्षण समाप्त कर दिए जाने की तारीख से भारत में आने वाले अगले पत्तन पर किसी दूसरे प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को प्रतिनियुक्त किए जाने की तारीख के बीच की अवधि, बशर्ते कि टनभार-कर चुनने वाली संबंधित कम्पनी ने ऐसा प्रशिक्षण समाप्त किए जाने के 30 दिन के भीतर उसके बारे में नौवहन-महानिदेशक को सूचित कर दिया हो।

12. (i) टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी, प्रशिक्षण आरंभ किए जाने के 30 दिन के भीतर नौवहन-महानिदेशक को प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी के संबंध में प्रशिक्षण की अनुसूचित अवधि और उस अर्हकारी जहाज / उन अर्हकारी जहाजों के बारे में सूचित कर देगी, जिस/जिन पर उसे रखा जाएगा और वह उपर्युक्त के संबंध में हुआ कोई बदलाव, 15 दिन के भीतर नौवहन-महानिदेशक को सूचित कर देगी।

(ii) टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी, प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर नौवहन-महानिदेशक को प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि और उस अर्हकारी जहाज / उन अर्हकारी जहाजों के बारे में सूचित कर देगी, जिस/जिन पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को तैनात किया गया था।

13. टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 45 दिन के भीतर, निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हुए नौवहन-महानिदेशक को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगी -

(क) खण्ड (1) के बारे में स्पष्टीकरण (ग) के अनुसार, वित्तीय वर्ष विशेष से संबंधित प्रशिक्षण से जुड़ी अपनी न्यूनतम अपेक्षा का परिकलन ;

(ख) उस अवधि का ब्यौरा जिसके दौरान वास्तव में प्रशिक्षण सुलभ करवाया गया और उसके साथ प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी के संबंध में प्रशिक्षण से संबंधित कार्य के दिनों से संबंधित जानकारी का सारांश ;

- (ग) वह अवधि, जिसे खण्ड 11 के अनुसार उस अवधि के रूप में माना गया जिसके दौरान प्रशिक्षण सुलभ करवाया गया;
- (घ) प्रशिक्षण से जुड़ी अपनी न्यूनतम अपेक्षा पूरी करने में रही कमी यदि कोई हो; और
- (ङ.) खण्ड 15 (i) के अनुसार, अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में आगे लायी जाने वाली कमी यदि कोई हो;
- (च) वह कमी जिसके संबंध में खण्ड 15 (ii)/ खण्ड 16 के अनुसार भुगतान किया जाना हो।

14. (i) जिस मामले में नौवहन-महानिदेशक खण्ड 13 के अनुसार वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत ब्यौरे से संतुष्ट नहीं हों तो वह उस मामले में टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी से यह अपेक्षा करते हुए उसे एक नोटिस देंगे कि वह उसमें विनिर्दिष्ट किसी ब्यौरे को ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत कर दे जो 30 दिन से कम नहीं हो और 60 दिन से अधिक नहीं हो तथा वह टनभार-कर चुनने वाली ऐसी कम्पनी को उसकी सुनवाई किए जाने का एक अवसर देंगे।

फिर भी, इस बारे में नौवहन-महानिदेशालय को कम्पनियों द्वारा गलत रिपोर्ट भेजे जाने पर नौवहन-महानिदेशालय को ऐसी कम्पनियों द्वारा भेजी गई ऐसी विवरणियों के मामले को फिर से देखने और उसकी फिर से छान-बीन करने और वह आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जो उचित समझी जाए।

(ii) टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के बारे में सुनवाई करने और उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण पर विचार करने के बाद, नौवहन-महानिदेशक टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा प्रशिक्षण से जुड़ी अपेक्षाओं का निर्वाह किए जाने की जाँच-पड़ताल करेंगे और यह दर्शाते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी करेंगे कि संबंधित वित्तीय वर्ष के संबंध में टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षाओं का निर्वाह किया गया है या नहीं तथा प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षाओं का निर्वाह नहीं किए जाने की स्थिति में वह उपर्युक्त प्रमाण-पत्र में प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम अपेक्षा का निर्वाह किए जाने में रही अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में आगे ले जायी जाने वाली कमी के दिनों की संख्या और ऐसी कमी के दिनों की संख्या दर्शाएंगे जिनके संबंध में खण्ड 15/16 के अनुसार अतिरिक्त भुगतान किया जाना होगा।

15. (i) टनभार-कर चुनने वाली किसी कम्पनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम अपेक्षा का निर्वाह किए जाने में, न्यूनतम अपेक्षा के 25 प्रतिशत तक रही किसी कमी के मामले में ऐसी कमी के दिनों की संख्या अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में आगे ले जायी जाएगी।

(ii) टनभार-कर चुनने वाली किसी कम्पनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम अपेक्षा का निर्वाह किए जाने में न्यूनतम अपेक्षा के 25 प्रतिशत से अधिक रही कमी के मामले में वह टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी, उपर्युक्त न्यास को उस प्रशिक्षण-शुल्क की धनराशि की 15 गुणी धनराशि का भुगतान करेगी जो उपर्युक्त न्यास को प्रशिक्षण से संबंधित दायित्व के निर्वाह में कोई भी कमी नहीं रहने पर प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों से मिलती ।

(iii) टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी, उप-नियम (ii) के अनुसार, उपर्युक्त आदेश मिलने की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद के ठीक अगले दिन से शुरू होने वाली और ऐसे दंड का भुगतान किए जाने के दिन समाप्त होने वाली अवधि में, प्रत्येक माह अथवा उपर्युक्त अवधि में शामिल माह के हिस्से के संबंध में एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने की दायी होगी ।

स्पष्टीकरण - इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रयोजन से, प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम अपेक्षा का निर्वाह किए जाने में पहले के किन्हीं वित्तीय वर्षों से आगे लायी गयी कमी पर प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम अपेक्षा के 25 प्रतिशत का परिकलन करने की दृष्टि से विचार नहीं किया जाएगा ।

16. टनभार-कर चुनने वाली किसी कम्पनी द्वारा अपने ही जलयानों की किसी किस्म विशेष अथवा अपने व्यापार के पैटर्न के कारण, प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षा का निर्वाह नहीं किए जा सकने की स्थिति में ऐसी टनभार-कर कम्पनी को उपर्युक्त न्यास को इस अधिसूचना के अनुसार, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किए जा पाने के फलस्वरूप, प्रशिक्षण शुल्क की उस धनराशि की 10 गुणी धनराशि का भुगतान करना होगा जो उपर्युक्त न्यास को प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों से, उन्हें प्रशिक्षण के लिए स्वीकार कर लिए जाने की स्थिति में प्रशासनिक लागत से संबंधित धनराशि के अतिरिक्त, मिली होती ।

17. इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षाएँ 01.01.2005 से लागू होंगी । यह अपेक्षा, इस वित्तीय वर्ष की शेष रही अवधि की आनुपातिक (यथानुपाती) होगी । यदि किसी नौवहन कम्पनी ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सुलभ करवाने के लिए पहले ही स्वीकार कर लिया हो तो ऐसे प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के प्रशिक्षण का, 01.01.2005 के बाद आगे जारी रखा जाना इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अनुपालन के रूप में माना जाए, बशर्ते कि 01.01.2005 से भुगतान किए जाने योग्य प्रशासनिक प्रभार का प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों और टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा 31.01.2005 को या उससे पहले भुगतान कर दिया जाए ।

18. नौवहन-महानिदेशक, टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी को कम से कम 10 दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, यह सत्यापित करने की दृष्टि से टनभार-कर चुनने वाली ऐसी कम्पनी के अभिलेखों की जाँच-पड़ताल कर सकते हैं कि उसके द्वारा वार्षिक विवरणी में दी गई जानकारी सही है या नहीं । टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी अपने अभिलेखों और प्रलेखन की जाँच-पड़ताल किए जा सकने और उसे सुकर बनाए जाने की दृष्टि से उपर्युक्त प्रणाली की व्यवस्था करेगी ।

टिप्पणी: नौवहन - महानिदेशक, विभिन्न प्रपत्रों और टनभार-कर चुनने वाली कम्पनियों द्वारा प्रशिक्षण से जुड़ी न्यूनतम अपेक्षाओं का निर्वाह किए जाने की व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने सहित अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में आगे अलग से और परिपत्र/अनुदेश अधिसूचित करेंगे।

[फा. सं. एस डी-11018/12/2002-एम डी]

सुशील कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2004

S.O. 1436(E).—In pursuance of Section 115VU of the Income Tax Act, 1961, the Central Government hereby notifies the following guidelines effective from 1st January, 2005 for providing training by Shipping Companies opting for Tonnage Tax scheme under Chapter XII-G of the Income Tax Act, 1961.

1. A tonnage tax company shall have trainee officers on board all or any of its Qualifying Ships and shall ensure that the aggregate of training man-days on all Qualifying Ships in a financial year is not less than the minimum training requirement.

Explanation:

For the purposes of these Guidelines,

(a) A 'trainee officer' means a person possessing the requisite qualifications specified under the Manual on Maritime Education & Training Assessment (META) published by the Director General of Shipping and / or as per guidelines prescribed by the Director General of Shipping, from time to time, to be a "trainee officer" to join on board a ship.

(b) The "Trust" means The 'Maritime Training Trust' settled by the Directorate General of Shipping in consultation with INSA.

(c) The 'minimum training requirement' for a financial year shall be:

(1) in case of ship owned or chartered-in by the tonnage tax company, (other than space or slot charters), the number of man-days shall be equivalent to the number of days for which such ships are operated by the tonnage tax company during the financial year multiplied by number of trainee officers required on such ships based on one (1) trainee officer for every ten (10) complement as per the Minimum Safe Manning Document or pro rata thereof:

(2) in case of space charters or slot charters, the number of man-days to be calculated by dividing the Net Tonnage of slot/space charters of the tonnage tax company by the Net Tonnage Factor and multiplying the result by number of days for which such ships are operated by the tonnage tax company during the financial year and shall include any shortfall of the immediately preceding financial year brought forward in accordance with clause 15.

Explanation 1: For the purpose of this clause, the Net Tonnage of slot/space charters shall be Net Tonnage as calculated under the notification issued in the official gazette vide Explanation to section 115 VG of the Income Tax Act, 1961.

Explanation 2: The 'Net Tonnage Factor' shall be the factor notified by the Director General of Shipping for each financial year calculated as the aggregate Net Tonnage of all qualifying ships registered under the Merchant Shipping Act, 1958 at the end of the preceding financial year divided by the total number of such ships at the end of the preceding financial year and shall be notified by the Director General of Shipping within 60 days from the beginning of each financial year.

(d) "Indian National Shipowners' Association" means the association of Indian ship-owners registered under section 25 of the Companies Act, 1956.

(e) 'Financial year' means the period beginning on April 1 and ending on March 31.

2. A tonnage tax company shall recruit trainee officers on board all or any of its qualifying ships from their own resources or from persons empanelled in the roster maintained by the Trust as a trainee-officer and shall provide the training in accordance with the Manual on Maritime Education & Training Assessment (META) and/ or as per training guidelines prescribed by the Director General of Shipping, from time to time.

3. All such trainee officers on board shall be in addition to the minimum safe manning document. Any trainee officer on the board of a Qualifying Ship shall not be taken into account for the purpose of determining the minimum safe-manning requirements prescribed by the Director General of Shipping.

4. The amount of training fees payable by such trainee-officer and the administrative cost payable by the trainee officer and the tonnage tax company to the Trust and stipend payable by the tonnage tax company to the trainee-officer shall be prescribed by the Director General of Shipping, from time to time.

5. The training fees payable by a trainee-officer to the Trust under clause (4) shall be paid in advance for six (6) months and such fees, together with administrative charges paid by a trainee-officer, shall be collected by the tonnage tax company in the name of the Trust and forthwith deposited with the Trust. It will be the responsibility of the tonnage tax company to so deposit the amount with the Trust not later than seven (7) working days from the receipt thereof and maintain the records for the same.

6. The Trust funds may be used for meeting all the administrative expenses relating to the Tonnage Tax cell to be created by the Director General of Shipping and for the promotion of training and employment of Indian seafaring officers and for payment towards refund of fees in accordance with clause 10.

7. The provision of training to a trainee-officer shall not be considered as guarantee of employment to such trainee-officer on completion or cessation of such training.

8. On completion of training by a trainee-officer, he shall be required to work with the tonnage tax company for such period, not exceeding one year, as may be required by the tonnage tax company. Until he completes this obligation, the trainee officer shall not be entitled to work with any other shipping company in the world and an undertaking to this effect shall be furnished by the trainee officer in favour of the Tonnage Tax company before being accepted for training, provided that this condition would not apply if the tonnage tax company does not offer him a job within a month of completion of training.

9. Where a trainee-officer on completion of training with a tonnage tax company, works with that tonnage tax company for a consecutive period of at least three years (subject to deducting leave periods), he shall be entitled to claim a refund of fees paid by him to the Trust on completion of such period of three years and such claim would be paid and settled by the Trust provided such claim is made within six months of the completion of the period of three years and on production of an appropriate certificate to that effect from the tonnage tax company.

10. If the trainee officer is not offered an employment for three consecutive years by the concerned tonnage tax company, the trainee officer is entitled to seek refund of the fees paid, provided such claim is made within six months of the date on which the employment or continued employment is not offered.

11. The following periods shall be deemed as the period during which training is imparted by the tonnage tax company -

(i) The period, when the requirements of a tonnage tax company for one or more trainee officers are not met due to non-availability of officers registered in the roster maintained by the Trust, starting from the date of acknowledgement by the Trust of a request in writing till the date of availability of trainee-officers in response to such request.

(ii) The period for which a trainee officer is absent on the board of a Qualifying Ship due to delay in reporting by the trainee-officer or a delay for any reason beyond the control of the tonnage tax company, where such delay has been intimated by the company to the Director General of Shipping.

(iii) Where the training is terminated due to any reason other than the scheduled completion of the training, the period between such termination and deputation of another trainee officer at the next port of call in India provided the tonnage tax company has given notice to the Director General of Shipping within 30 days of such termination.

12. (i) The tonnage tax company shall intimate the Director General of Shipping about the scheduled period of training in respect of each of the trainee officers and the Qualifying Ship(s) on which he would be deployed, within 30 days of the start of training and any change therein, within fifteen (15) days.

(ii) The tonnage tax company shall intimate the Director General of Shipping about the actual period of training as well as the Qualifying Ship(s) on which each trainee officer was deployed within 30 days of the date of completion of training.

13. The tonnage tax company shall furnish an annual return to the Director General of Shipping within 45 days of the end of the financial year, providing the following details -

(a) The calculation of its minimum training requirement for the financial year in accordance with Explanation (c) to clause (1);

(b) The period for which it has actually imparted training supported by a summary of the man-days of training with respect of each of the trainee officer;

- (c) The period for which it is deemed as imparting the training under clause 11;
- (d) The shortfall, if any, in meeting its minimum training requirement; and
- (e) The shortfall to be carried-forward, if any, under clause 15(i) to the subsequent financial year.
- (f) The shortfall for which payment has to be made under clause 15(ii)/clause 16

14. (i) Where the Director General of Shipping is not satisfied with the details submitted in the annual return in accordance with clause 13, he shall serve on the tonnage tax company a notice requiring it to produce within such time, not being less than 30 days and not being more than 60 days, any particulars specified therein and shall provide an opportunity of hearing to the tonnage tax company.

However, in case of any mis-reporting by companies on this account Directorate General of Shipping shall have the right to reopen and reinvestigate the case and take necessary action as deemed fit.

(ii) After hearing such evidence and after taking into account such particulars as the tonnage tax company may produce, the Director General of Shipping shall determine the compliance by the tonnage tax company of the training requirements and shall issue a certificate stating whether or not the tonnage tax company has complied with the training requirements in respect of the relevant financial year and in case of non-compliance, specifying the number of days of shortfall in meeting the minimum training requirement to be carried forward to the subsequent financial year and the number of days of shortfall in relation to which additional payment may be payable in accordance with clause (15)/clause (16).

15 (i). In case of a shortfall in meeting the minimum training requirement by a tonnage tax company for any financial year is upto twenty five percent of the minimum requirement, the number of days of such shortfall shall be carried-forward to the subsequent financial year.

(ii) In case of a shortfall in meeting the minimum training requirement by a tonnage tax company exceeding twenty-five percent of the minimum training requirement for any financial year, the tonnage tax company shall pay to the Trust 15 times the training fees that the Trust would have received from trainee officers, if there was no shortfall in lieu of the obligation for training.

(iii) The tonnage tax company shall be liable to pay simple interest at one percent for every month or part of a month comprised in the period commencing from the day immediately following the expiry of 30 days from the date of receipt of the order under sub-rule (ii) and ending with the day on which such penalty payment is made.

Explanation- For the purpose of these Guidelines, any shortfall in meeting the minimum training requirement brought forward from any preceding financial years shall not be considered for calculating twenty-five percent of the minimum training requirement.

16. In the event that the tonnage tax company is not in a position to meet any training requirement by virtue of the type of vessels it owns or its trading pattern, such tonnage tax company shall pay Ten (10) times such training fees that the Trust would

have received from trainee officers, if they had been accepted for training, in addition to the administrative cost to the Trust in lieu of their obligation hereunder. The Directorate General of Shipping shall on the merit of each case grant exemption to the Tonnage Tax Company on not being able to meet the minimum training requirement and opt to pay fees as provided hereunder, in lieu of training.

17. Training requirements under these guidelines shall be applicable from 01-01-2005. The requirement would be proportional to the balance period of the financial year. If any shipping company has already accepted trainees, the continuance of such trainee officers, after 01-01-2005, may be accepted as a compliance under these guidelines, provided that the administrative charges and fees payable from 01-01-2005 is paid by the trainee officers and the tonnage tax company on or before 31-01-2005.

18. The Director-General of Shipping after giving notice in writing of not less than ten days to the tonnage tax company, can examine the records of such tonnage tax company to verify that the information given in relation to the annual return is correct. The tonnage tax company shall make provision for a suitable system to enable and to facilitate the checking of its records and documentation.

Note: The Director General of Shipping will notify the further circular/instructions on other relating aspects including various forms and describing the system for administering the minimum training requirements by tonnage tax companies separately.

[F.No.SD-11018/12/2002-MD]

SUSHEEL KUMAR, Jt. Secy.